परमाणु वैज्ञानिक डॉ. अनिल काकोडकर ने आइआइटी में कहा-

रूरल डवलपमेंट के बिना भारत नहीं बन सकता विश्वगुरु

शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक विकास के लिए आइआइटी को करना होगी ग्रामीण क्षेत्र के संस्थानों से सहभागिता

पत्रिका PLUS रिपोर्टर

इंदौर ● देश में युवाओं की ज्यादा संख्या ग्रामीण क्षेत्रों से है, इसलिए इनकी क्षमता में वृद्धि करनी होगी। गांव में कई संभावनाएं हैं। आइआइटी और अन्य संस्थाओं में अब सहभागिता होने लगी है। इस तरह की सहभागिता से क्या हम ऐसा इकोसिस्टम बना सकते हैं, जहां ग्रामीण युवा कुछ इनोवेटिव करें। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। साथ ही साथ उन क्षेत्रों के लोगों की आजीविका बढ़ाने, स्थानीय समस्याओं के समाधान ढूंढने में मदद मिल सकती है। अगर हम यह करते हैं तो हम असल में ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर बदलने में योगदान दे रहे हैं। गांव में भी एक इकोसिस्टम तैयार करना होगा। आइआइटी मद्रास ने इस तरह का इकोसिस्टम विकसित किया है। लेकिन चीन में इस तरह के 300 से ज्यादा इकोसिस्टम हैं। हमें कम से कम 20 से 25 तैयार करने होंगे। पैसे नहीं सोसायटी के लिए काम करें। नैतिक मूल्यों को अपनाएं। ऐसा विकास करना है, जो समावेशी हो और गांव तक समृद्धि पहुंचाए। तभी भारत पूर्व की तरह विश्वगुरु बन पाएगा। यह बातें परमाणु वैज्ञानिक पद्मश्री डॉ. अनिल काकोडकर ने आइआइटी इंदौर में कही। वे यहां देश के विकास में आइआइटी की भूमिका पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमारी जीडीपी भले ही दुनिया में सबसे तेज गति से चल रही हो, लेकिन जब तक प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ती, मेरा मानना है विकास नहीं हुआ।

बिलियन डॉलर स्टार्टअप में आइआइटी चौथे नंबर पर : अमरीकन पॉलिसी ब्रीफ की मार्च 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक आइआइटी दुनिया में बिलियन डॉलर स्टार्टअप (12) देने के मामले में चौथे नंबर पर है। स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी 51 स्टार्टअप के साथ टॉप पर है। दूसरे पर हॉवर्ड (37) और तीसरे पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया (18) है।

देश के सामने ये हैं 10 सबसे बड़ी चुनौतियां

1. पोषण सुरक्षा की गारंटी, एनीमिया खत्म करना।
2. नदी और अन्य वॉटर बॉडीज में पानी की गुणवत्ता और संख्या सुनिश्चित करना।
3. देश के क्षेत्रफल अनुरूप महत्वपूर्ण संसाधनों को सुरक्षित करना।
4. राष्ट्रीय जलवायु पैटर्न को समझना और अनुकूलित करना।
5. भारत को गैर जीवाश्म इंधन आधारित बनाना।
6. रेलवे को लेह और तवांग तक ले जाना।
7. स्वतंत्र चुनाव और वित्तीय सशक्तिकरण की क्षमता सुनिश्चित करना।
8. सभी के लिए वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य विकेंद्रीकृत और वितरित ऊर्जा का विकास करना।
9. यूनिवर्सल इको-फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट सुनिश्चित करना।
10. भाषा तटस्थ, समग्र शिक्षा प्रदान करना।

रिसर्च में खर्च ज्यादा, रिजल्ट कम

हमारे देश में जीडीपी का महज 0.2 फीसदी ही रिसर्च और डवलपमेंट पर खर्च हो रहा है, लेकिन यह राशि इजराइल, कनाडा, स्वीडन, यूके, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड जैसे देशों से ज्यादा है। इसके बावजूद हमें इन देशों से तकनीक आयात करनी पड़ती है। दुनिया में उसी देश की चलती है, जो तकनीक में एडवांस हो। इसलिए हमें तकनीकी रूप से सक्षम होना पड़ेगा और यह तब तक संभव नहीं है जब तक हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा नहीं हो।

अटल जैसा बोल्ड पीएम नहीं मिल सकता

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के पूर्व निदेशक डॉ. काकोडकर ने 1974 और 1998 में किए गए परमाणु परीक्षण में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा, उनके जैसा दूरदर्शी और बोल्ड पीएम कोई दूसरा नहीं मिल सकता। जब परमाणु परीक्षण की अनुमति की बात आई तो उन्होंने निर्णय लेने में एक सेकंड भी नहीं लगाया और कहा...करो।

एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट्स से फ्यूल बने तो मिलेगा सस्ता पेट्रोल

ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल आदि की छंटनी के बाद जो बाय प्रोडक्ट बचता है, उसमें से कुछ तो जानवरों के लिए होता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ शेष रहता है। आज हमारे पास हर प्रोडक्ट से एथोनॉल बनाने की तकनीक है। अगर हम ऐसी व्यवस्था करें कि सभी बायोमास फ्यूल में बदलें तो हाइड्रोकार्बल आयात करने से बचा जा सकता है। हालांकि ये थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन अगर क्रूड के दाम दोगुने हो गए तब क्या करेंगे? अगर हमने 5 फीसदी बायोमास से भी फ्यूल बना लिया तो फिर अंतरराष्ट्रीय कीमत बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भी बढ़ोतरी होगी।

Patrika (Indore), Patrika Plus, 25.08.2018, Page-17